



अजमेर

Rashtradoot

फोन:- 2627612, 2427249 फैक्स:- 0145-2624665

वर्ष: 36

संख्या: 230

प्रभात

अजमेर, सोमवार 30 मार्च, 2026

आर.जे./ए.जे./73/2015-2017

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

सऊदी अरब एयरबेस पर हमला, अमेरिकी वायुसेना का अत्याधुनिक विमान नष्ट

ईरान ने इस हमले में 6 बैलिस्टिक मिसाइल व 29 हथियारों से लैस ड्रोन का उपयोग किया

तेहरान, 29 मार्च। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध अब पांचवें सप्ताह में पहुंच गया है। रविवार को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान की तरफ से किए गए मिसाइल और ड्रोन के बड़े हमले में अमेरिकी वायुसेना का अत्याधुनिक ई-3 ए.इब्ल्यू.एसी.एस. जासूसी विमान अर्वाकस पूरी तरह नष्ट हो गया। आईआरजीसी ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि उसने अमेरिका के ईंधन भरने और हवाई सहायता बेड़े को निशाना बनाया, जिसमें कई बेड़े सैन्य विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार संस्था तसनीम न्यूज एजेंसी ने इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) के हवाले से यह जानकारी दी।

विश्लेषण में सामने आया है कि हमला बेहद सटीक था और विमान

- विशेषज्ञों के अनुसार, हमला बेहद सटीक था और विमान के सबसे अहम हिस्से, रडार को निशाना बनाया गया। यह भाग विमान की मुख्य ऑपरेशनल क्षमता का केन्द्र है।

के सबसे अहम हिस्से रडार डोम को निशाना बनाया गया। यह वही भाग होता है जिसमें एएन/एपीवाई-2 सर्विलांस रडार सिस्टम लगा होता है, जो विमान की मुख्य ऑपरेशनल क्षमता का केंद्र है। तस्वीरों में विमान के पिछले हिस्से में भारी संरचनात्मक क्षति देखी गई है। यह विमान हाल ही में 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के तहत इस बेस पर तैनात किया गया था और अमेरिकी वायुसेना की 552वीं एयर कंट्रोल विंग का हिस्सा था। इस घटना के बाद अमेरिकी -3 बेड़े में विमानों की संख्या 16 से घटकर 15 रह गई है।

अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हमले में छह बैलिस्टिक मिसाइलों और 29 हथियारों से लैस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में कम से कम 15 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है। आईआरजीसी ने आगे कहा कि जिस विमान को निशाना बनाया गया वह पूरी तरह से नष्ट हो गया और पास में खड़े अन्य विमानों को भी काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकोम) ने अभी तक हमले के पूरे विवरण की आधिकारिक

पुष्टि नहीं की है लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, ई-3जी सेंट्री अवाक्स विमान अमेरिकी वायु सेना का एक महत्वपूर्ण हवाई चेतावनी और युद्ध प्रबंधन प्लेटफॉर्म है, जो 250 मील से अधिक दूरी तक निगरानी करने में सक्षम होता है। इसके नष्ट होने से क्षेत्र में अमेरिकी हवाई निगरानी और कमान क्षमता पर बड़ा असर पड़ सकता है।

अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर संयुक्त रूप से 28 फरवरी को हमला किया था जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के साथ ही कई वरिष्ठ सैन्य कमांडरों और नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके जवाब में, ईरान ने कार्रवाई करते हुए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन की लहरों से निशाना बनाया, जिससे व्यापक क्षति पहुंची है।

अमेरिका के सभी 50 राज्यों में ट्रंप के खिलाफ रैलियां निकलीं

वाशिंगटन डीसी, 29 मार्च। ईरान युद्ध और राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की कार्रवाइयों के विरोध में शनिवार को अमेरिका के सभी 50 राज्यों और यूरोप के कई हिस्सों में “नो किंग्स” रैलियों में भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, लोग

- “नो किंग्स” रैली में 80 लाख से अधिक लोगों ने ईरान युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन किया।

कई मुद्दों पर अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए इकट्ठा हुए। ‘नो किंग्स रैली’ में 80 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूरे अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 3,300 से ज्यादा स्थानों पर ये प्रदर्शन आयोजित किए गए। अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पेट्रोलियम में हुए पिछले नो किंग्स प्रदर्शनों की तुलना में इस बार करीब 10 लाख ज्यादा लोग शामिल हुए और लगभग 600 ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका के साढ़े तीन हजार मरीन मध्य पूर्व पहुँचे

वाशिंगटन, 29 मार्च। अमेरिका के 3500 अतिरिक्त सैनिक मध्य पूर्व पहुंच चुके हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इन सैनिकों को यूएसएस टिफली जहाज से भेजा गया है। सभी सैनिक 31वीं मरीन एक्सपेंडिशनरी यूनिट का हिस्सा हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान और हथियार भी भेजे गए हैं। अमेरिका ने ईरान पर जमीनी सैन्य अभियान शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है।

चीन की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस सेंट्रल कमांड

- माना जा रहा है कि अमेरिका का यह कदम जमीनी सैन्य अभियान की तैयारी का हिस्सा है।

ने शनिवार को घोषणा की कि 3,500 मरीन और नाविकों का टास्क फोर्स शुक्रवार को मध्य पूर्व पहुंच गया है। कमांड ने एक्स पर संक्षिप्त पोस्ट में कहा, "यूएसएस त्रिपोली (एलएचए 7) पर सवार यूएस नाविक और मरीन 27 मार्च को कमांड के जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में पहुंच गए।" पोस्ट में बताया गया कि इन सैनिकों के पास परिवहन, स्ट्राइक फाइटर विमान और एम्फीबियस असॉल्ट व टैक्लिकल संसाधन भी मौजूद हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका ने विदेशी प्रोफेशनल्स के न्यूनतम वेतन में भारी वृद्धि की

इससे विदेशी प्रोफेशनल्स को अमेरिका में नौकरी देना कंपनियों के लिए महंगा हो जाएगा तथा शायद अमेरिकी नागरिकों को ये नौकरियाँ मिल जाए

- इस नई नीति का सबसे ज्यादा असर भारतीय मूल के इंजीनियर, आई.टी. वर्कर्स पर पड़ेगा, क्योंकि एच-1बी वीजा के मार्फत अमेरिका में लगभग 2.8 लाख भारतीय काम कर रहे हैं। पर, अब भारतीय इंजीनियर्स आदि का अमेरिका में काम करने का रास्ता और सड़का हो जाएगा।
- इसका भारत को एक लाभ तो है कि अब ये प्रोफेशनल्स, भारत लौटने को मजबूर हो जाएंगे तथा भारत के लोकल “टैलेंट पूल” को मजबूती मिलेगी तथा स्टार्टअप, वित्तीय टेक्नॉलजी व डिजिटल सर्विसेज सेंक्टर को लाभ पहुंचेगा।
- पर, दूसरी ओर एक तत्कालिक नुकसान भी है। भारतीय प्रोफेशनल्स द्वारा, भारत को भेजे जा रहे “रैमिटेस” (वेतन आदि) में काफी कमी आएगी, क्योंकि नौकरी जाने के बाद काफी भारतीय प्रोफेशनल्स भारत लौटने को होंगे।

प्राथमिकता दें। सिद्धांत रूप में यह ट्रम्प काल की संरक्षणवादी नीतियों के अनुरूप है। हालांकि, व्यवहार में यह कदम उस संतुलित वैश्विक प्रतिष्ठा के व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यूआई व बहरीन में दो बड़ी फैक्ट्रियों को ईरान ने निशाना बनाया

ये दोनों फैक्ट्री अमेरिकी सैन्य व एयरोस्पेस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण उत्पादन करती थीं

तेहरान, 29 मार्च। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी स्थित संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में अमेरिकी सैन्य और एयरोस्पेस उद्योगों से जुड़ी दो औद्योगिक फैक्ट्रियों को निशाना बनाया।

केन्द्र सरकार ने केरोसिन की सप्लाई में भी ठील दी

नई दिल्ली, 29 मार्च। होर्मुज संकट और वैश्विक तनाव के बीच भारत सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रॉयटर्स की जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने केरोसिन यानी मिट्टी के तेल

- ऊर्जा संकट के बीच इस कदम से आम आदमी को राहत मिलेगी।

की सप्लाई आसान बनाने के लिए नियमों में ढील दी है। इसका मकसद है कि जिन इलाकों में गैस या बिजली की कमी है, वहां लोगों को खाना बनाने और रोशनी के लिए तुरंत केरोसिन मिल सके। सरकार ने साफ किया है कि पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंस से जुड़े कुछ नियमों को अस्थायी तौर पर आसान किया गया है। इससे 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरत के हिसाब से केरोसिन की सप्लाई की जा सकेगी।

सरकार का कहना है कि इस कदम से आम लोगों को सीधा फायदा होगा। खासकर ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में जहां अभी भी लोग केरोसिन पर निर्भर हैं। सरकार ने कहा कि जरूरत पड़ने पर तुरंत केरोसिन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि किसी को खाना बनाने या रोशनी के लिए परेशानी न हो। यह फैसला अस्थायी है, लेकिन हालात सामान्य होने तक इसे जारी रखा जाएगा।

- यूआई की ईमाल फैक्ट्री विश्व की सबसे बड़ी एल्युमीनियम उत्पादन लाइन है तथा बहरीन की अल्बा फैक्ट्री में अमेरिकी कंपनियों का निवेश व हिस्सेदारी भी है।

आईआरजीसी के अनुसार यह कार्रवाई अमेरिका-इजरायल की ओर से किए गए हमले के जवाब में की गई है जिसमें मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार संस्था तसनीम न्यूज एजेंसी ने आईआरजीसी के हवाले से उक्त जानकारी दी।

आईआरजीसी ने एक बयान में कहा कि फ़ारस की खाड़ी के दक्षिणी तटीय राज्यों के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के अमेरिका और इजरायल के दुर्भावनापूर्ण कार्यों के बाद आईआरजीसी एयरोस्पेस फ़ोर्स और नौसेना के लड़ाकों ने एक हाइब्रिड और

लक्षित अभियान चलाया। उन्होंने इस क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य और एयरोस्पेस उद्योगों से जुड़ी दो फैक्ट्रियों-यूआई में एमिरेट्स एल्युमीनियम (ईमाल) फैक्ट्री और बहरीन में एल्युमीनियम बहरीन (अल्बा) फैक्ट्री को निशाना बनाया है। ईमाल फैक्ट्री में दुनिया की सबसे लंबी एल्युमीनियम उत्पादन लाइन है, जिसकी उत्पादन क्षमता 1.3 मिलियन टन है। वहीं, अल्बा एल्युमीनियम फैक्ट्री में अमेरिकी कंपनियों का निवेश और हिस्सेदारी है जो अमेरिका के सैन्य उद्योगों के लिए सामान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

स्टेनोग्राफर भर्ती में कर्मचारी चयन बोर्ड की अतिरिक्त रियायत खारिज

हाईकोर्ट ने कहा कि, 444 पदों की इस भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग 45 दिनों में नई मैरिट लिस्ट बनाए

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर, 29 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर एंड पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड-2 भर्ती के दूसरे फेज के दौरान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को गलतियों में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त राहत देने के फैसले को चुनौती दी गई। सचिवालय के लिए 444 पदों की इस भर्ती की विज्ञप्ति 26 फरवरी 2024 को जारी हुई थी, जिसकी मैरिट लिस्ट 25 सितंबर 2025 को जारी की गई थी।

अदालत ने इस भर्ती को लेकर दायर की गई 40 याचिकाओं को एक साथ सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता संदीप पाठक ने अदालत को बताया कि, इस भर्ती की चयन प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया था। प्रथम चरण में कई तरह के लिखित परीक्षाएं थी, जबकि दूसरे चरण में स्टेनोग्राफी टेस्ट था। प्रथम चरण में हर अभ्यर्थी को 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना था, तभी वह दूसरे चरण के लिए पात्र माना जाएगा।

- अदालत ने सवाल उठाया कि, जब 5 प्रतिशत की अतिरिक्त राहत दिए बिना भी 643 अभ्यर्थी पात्र थे, फिर इनमें से 444 पद क्यों नहीं भरे गए?
- याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 904 अभ्यर्थियों ने मैरिट लिस्ट में स्थान पाया है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5 प्रतिशत की अतिरिक्त राहत गैरकानूनी तरीके से दी है।

कि, कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य सरकार ने गैरकानूनी ढंग से अभ्यर्थियों को फेज-2 में 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत अतिरिक्त गलतियों व त्रुटियों पर राहत दी, जबकि नियमानुसार गलतियों में राहत केवल सामान्य वर्ग में

20 प्रतिशत तथा एससी-एसटी वर्ग को 25 प्रतिशत दी जाती है। उन्होंने कहा कि, 5 प्रतिशत अतिरिक्त राहत का प्रावधान तभी लागू किया जाता है, जब भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या तय वैकेंसी से कम रहे।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 904 अभ्यर्थियों में से 643 अभ्यर्थी ने फेज 2 प्रतिशत की अतिरिक्त राहत देने का कोई औचित्य नहीं था। कमांड ने कहा कि, अगर चयन बोर्ड कोई वैटिंग लिस्ट भी बनाना चाहता था तो वह सूची भी इन 643 अभ्यर्थियों में से ही बनाई जा सकती थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्कों को स्वीकारते हुए कहा कि, 25 सितंबर और 21 अक्टूबर 2025 को जारी मैरिट लिस्ट तथा अंतरिम मैरिट सूची को खारिज किया जाता है। उन्होंने आदेश दिए कि अब कर्मचारी चयन बोर्ड 45 दिनों में नई मैरिट सूची बनाए, जिन्हें 5 प्रतिशत की अतिरिक्त रियायत का फायदा नहीं दिया गया है।

अभ्यर्थी थे, जिनमें से रिक्त पदों की भर्ती की जा सकती थी। ऐसे में अतिरिक्त राहत देने का कोई औचित्य नहीं था। अदालत ने कहा कि, अगर चयन बोर्ड कोई वैटिंग लिस्ट भी बनाना चाहता था तो वह सूची भी इन 643 अभ्यर्थियों में से ही बनाई जा सकती थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्कों को स्वीकारते हुए कहा कि, 25 सितंबर और 21 अक्टूबर 2025 को जारी मैरिट लिस्ट तथा अंतरिम मैरिट सूची को खारिज किया जाता है। उन्होंने आदेश दिए कि अब कर्मचारी चयन बोर्ड 45 दिनों में नई मैरिट सूची बनाए, जिन्हें 5 प्रतिशत की अतिरिक्त रियायत का फायदा नहीं दिया गया है।

- बर्फ और बरसात ने सड़कों पर फिसलन बढ़ाई, रोहतांग दर्रा आंशिक रूप से बंद।

प्रशासन ने यात्रियों को फिसलन भरी सड़कों पर सावधानी से वाहन चलाने की सलाह जारी की है। जिला आपात रिपोर्ट के अनुसार कई ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो गए हैं। रोहतांग दर्रा और कुंजुम दर्रा सहित प्रमुख मार्गों पर आवाजाही ठप है। रोहतांग मार्ग के आंशिक रूप से बंद होने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)